market availability and other related factors.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5564. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने कौन से नये कदम उठाए हैं;

(ख) सरकार ने वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने और इसे कारगर बनाने के लिए क्या व्यवस्था की है और क्या उपभोक्ताओं को इस प्रणाली में शामिल करने की कोई योजना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी योजना बनाने का है जिसके अन्तर्गत इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे जायें तथा उनकी जांच की जाये और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) अपने-अपने इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नयी उचित दर की दुकानें खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाना है, जिसमें दूर-दराज के इलाकों के लिए चलती-फिरती दुकानें और औद्योगिक मजदूरों आदि के लिए दुकानें खोलना भी शामिल है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से यह भी कहा गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की समय-समय पर पुनरीक्षा करें और इस प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनायें। राज्य सरकारों का ध्यान यह सुनिश्चित करने की ओर भी दिलाया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की वसूली, ढुलाई, भण्डारण और वितरण में अधिक तालमेल स्थापित करने, अतिरिक्त बिक्री केन्द्र खोलने, सहकारी समितियों की भूमिका बढ़ाने, विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता सलाहकार समितियों का गठन करने और जिला प्रशासन तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

केन्द्र में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की समय-समय पर पुनरीक्षा करने के लिए नागरिक पूर्ति मंत्री जी की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद बनायी गयी है। यह परिषद् समय-समय पर अपनी बैठकें आयोजित करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर सरकार को सलाह देती है तथा सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा वितरण प्रबन्ध में सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव देती है। राज्यों द्वारा भी विभिन्न स्तरों पर इसी प्रकार की समितियों का गठन किया जाना है, जिनमें विधायक, उपभोक्ताओं आदि के प्रतिनिधि शामिल किये जाने हैं। इस प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव या तो इन समितियों को या फिर सीधे केन्द्रीय और राज्य सरकारों को दिये जा सकते हैं।

Number of Problem Villages for Providing Drinking Water

5565. SHRI ANANTHA RAMULU MALLU : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the number of problem villages in the State of Andhra Pradesh which